पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन समाप्त हो और शीघ्रातिशीघ्र वहां पर चुनाव कराय जायें ताकि डेमोक्रेटिक एटमास्फियर बन सके और जनतांत्रिक परम्परा का प्रशासन कायम हो सके तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

श्री चरण सिंह : हमारी तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि जैसे ही बरसात खत्म हुई हम एलेक्शन का प्रबंध करेंगे ।

श्री केशवराव धोंगड़े : डिप्टी स्पीकर साहब, इंग्लैण्ड के अखबारों के अन्दर प्राइम मिनिस्टर साहब के इन्टरव्यू के खिलाफ़ जो कुछ लिखा है, उस के खिलाफ क्या हमारे हाई-कमिश्नर की तरफ़ से या गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कोई स्पष्टीकरण किया गया था ?

श्री मोरारजी देसाई : वहां किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है ।

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: If Mr. Phizo has not approved of the Shillong Agreement, what is new in the present statement of that gentleman?

श्री चरण सिंह : फीजो साहब ने शिलांग एग्रीमेन्ट से असहमति प्रकट की है । वे कह रहे हैं कि नागालैंड एक इण्डिपन्डेन्ट कन्ट्री है । उन्होंने डिफिकिल्टीज-विटविन-दि-टू-पीपल्स-आफ-अवर टू कन्ट्रीज की बात कही है ।

He wanted to see the Prime Minister in order to resolve the difficulties between the two people. There is no question of his approving the Shillong Agreement.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Some time back, it was reported that there was some change in the attitude of Mr. Phizo, and that he was prepared to come back to India. What has been the reason recently for another change in his attitude? Could the Government of India enlighten us on this? Secondly, when there was a talk between the Prime Minister and Mr. Phizo in London, did the Prime Minister also refer to the foreign assistance that they were seeking or getting? And if he did what was the reply of Mr. Phizo with regard to it; and finally, has there been any change so far as the training of Nagas in China is concerned, after the improvement in our relations with China? These are the three aspects of the matter on which we would like to know more.

SHRI MORARJI DESAI: The reported change in Mr. Phizo was wrongly reported. That is all that I can say. There was no change in him; and I don't think there will be any change in him. He will understand things only when he sees that there is no support for him generally; then alone he will come round. That is my estimate. I think that is going to happen soon.

भूतपूर्व सैनिकों के लिये पेंशन

*547. **श्री यशदत्त शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की दरें पांच वर्ष पूर्व या उससे पहले निर्धारित की गई थीं;

(ख) क्या बदली हुई वर्तमान परिस्थितियों में सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन दरों पर पुनर्विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अफसर पद से नीचे के कार्मिकों और अफसरों के लिए पेंशन की दरों में क्रमश : 1975 में और 1976/77

में संशोधन किये गए थे । ये संशोधित दरें उन सभी सेवा कार्मिकों पर लागू होती हैं जो 1-1-1973 को अथवा उस के पश्चात् सेवा निवृत्त हुए हैं ।

(ख) और (ग). ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नही किया जा रहा है ।

श्री यशवन्त शर्मा : मंत्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि उपभोग्य पदार्थों की खुदरा और थोक दरों मे असामान्य वृद्धि हुई है, चाहे इस के लिए पिछली सरकार की नीतियां जिम्मेदार हों । जब इस तरह की रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़े है, तो क्या मंत्री महोदय इन छोटे सैनिकों की कठिनाइयों को महसूस करते हुए उन की पन्शन की दरों में वृद्धि की नीति पर विचार करेंगे ? यदि करेंगे, तो कृपा कर बताइये कि उस दृष्टि मे कब तक वे ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैंने अभी बताया है, 1975 और 1976-77 में संशोधन किया गया है । सदन को स्मरण होगा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि पेंशन में कुछ वृद्धि करने के लिए लोगों की मांग है और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि उस पर विचार किया जायेगा । अगर उस पर विचार करके असैनिक कर्मचारियों और अफसरों की पेंशन में कुछ वृद्धि मिली तो उसी हिसाब से सैनिक कर्मचारियों और अफसरों को भी दी जायगी ?

श्री यशवन्त शर्मा : पिछली वृद्धियों के सम्बन्ध में मेरा ऐसा अनुमान रहा है कि बड़े अफसरों को पेंशन में तो अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन छोटे सैनिकों को उसी अनुपात से लाभ नहीं मिला है । क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध मे भविष्य में कोई निर्णय लेते समय छोटे सैनिकों की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए जो इस मंहगाई का अधिक शिकार हैं, इस पर विचार करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : यह जो निष्कर्ष सदस्य महोदय ने निकाला है, वह तथ्य नहीं है । सैनिक कर्मचारियों की पेंशन भी, जो अफसर के नीचे के पदों पर है, उसी हिसाब से निर्धारित की जाती है जैसी असैनिक कर्मचारियों कि को जाती है । फर्क यह पड़ता है कि सैनिक कर्मचारियों को नौकरी मे पांच वर्ष का वेटेज दे कर पेंशन दी जाती है और अफ़सरों को, क्योंकि वे नौकरी से पहले रिटायर हो जाते है, अवधि के हिसाब से 5 या 9 वर्ष तक का वेटेज दिया जाता है और तब उन की पेंशन निर्धारित की जाती है ।

डा० कर्ण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन के प्रति सारे देश की सहानुभूति ही नहीं है बल्कि सभी उन के कृतज्ञ है क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन के सब से अच्छे वर्ष देश की रक्षा के लिए अर्पित किए है । जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा है उन की पेंशन से वृद्धि तो होनी ही चाहिए लेकिन इस के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए और बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं । जो रजर्वेशन नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है, मेरा यह विचार रहा है कि वह उन को पूरे तौर पर मिलता नहीं है । पूरे देश में जितना उन को मिलना चाहिए उतना उन को नहीं मिलता है । इस के अलावा उन के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों की बहुत आवश्यकता होती है और इण्डियन सोलजर्स, सेलर्स एण्ड एयरमैन बोर्ड ने इस बारे में बहुत सारे सुझाव रखे हैं । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जितनी कठिनाइयां

और कष्ट भूतपूर्व सैनिकों के सामने आते हैं, उन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और बहुमुखी स्तर पर विचार करने की कोई योजना उन के पास है ?

श्री जगजीवन राम : यह मेरे अधिकार में तो नहीं है कि मै यह कहूं कि यह प्रश्न इस से पैदा नही होता है क्योंकि यह तो पेंशन का मामला है कि पेंशन पर गए हुए लोगो को क्या मदद दी जाए, लेकिन मैं यह बताना चाहता हू कि जो सैनिक या अधिकारी फौज से रिटायर कर चुके ह उन के लिए एक सलाहकार समिति है, जिस में भूतपूर्व सैनिक अधिकारी और सदन के सदस्य भी है । समय-समय पर उन से सलाह ली जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत कठिन प्रश्न है कि जितने भी लोग फौज से निकलेंगे सभी को काम पर लगा दिया जाएगा । यह कठिनाई भी होती है कि जहां संरक्षण रखा हुआ है योग्यता के हिसाब से उन सैनिक अधिकारियों को ठीक नहीं पाया जाता है। बहुत जगहों पर ग्रेजुएट की मांग होती है लेकिन हमारे यहां अधिकांश अधिकारी ग्रेजुएट नही हैं । इस के अलावा जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वह भी उनको नहीं होती है । माननीय सदस्य महोदय को शायद मालूम है कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जो अधिकारी रिटायर किए गए है उन को इस तरह का प्रशिक्षण दे दिया जाय और बहुत से लोगों ने हैदराबाद और दूसरे स्थानों पर प्रशिक्षण हासिल भी किया है । कुछ सैनिको के लिए भी यह प्रबन्ध किया गया है कि रिटायर होने के छः महीने पहले उन को किसी न किसी ट्रेड में प्रशिक्षित कर दिया जाए जिस से बाहर निकलने पर अगर उन को कोई नौकरी न मिले तो वे कम से कम कुछ अपना काम आरम्भ करके अपनी जीविकोपार्जन कर सकें । अब समय ऐसा आ गया है जब जमीन पर बसाना केवल कल्पना मात्र रह जाएगा । फालतू जमीन अब उपलब्ध नही है । वह सेचुरेशन प्वाइन्ट पर पहुंच चुकी है । इसलिए ऐसा प्रबन्ध कर रहे है कि निजी रोजगार में अधिक से अधिक लोगों को लगाया जाय और इस के लिए अफसरों तथा सैनिकों दोनों के लिए प्रशिक्षण का इन्तजाम हो ।

चौधरी बलबीर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 1973 के पहले जो पेंशन लेने वाले हैं और 1973 के बाद जो पेंशन लेने वाले है और एक ही ओहदे के हैं, 1973 के बाद वालों को यादा पेंशन मिलती है और उस से पहले वालो को कम मिलनी है ? क्या सरकार इस फ़र्क को दूर करने की कोशिश करेगी ?

श्री जगजीवन राम : जी नही कोई भी तिथि मानेंगे, तो फर्क होगा ही । 1973 से रिटायर होने वाले लोगों को बढ़ी हुई पेंशन मिली । इसलिए जो 1973 से पहले रिटयार हुए है, उन को पेंशन में कुछ फर्क है ही ।

चौधरी बलबीर सिंह : उन लोगों का रैंक तो एक हो रहा है ।

श्री जगजीवन राम : वह तो ठीक है लेकिन सब जगहों में तनख्वाहें भी एकसी नहीं होती है । वे भी कम और ज्यादा हो जाया करती हैं । इसलिए उस को पूरा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

SHRI A. C. GEORGE: We all speak with sypathy for the jawans, but in practice what we find is that the moment they retire, they go into oblivion and all of us forget them. These

ex-servicemen, or veterans as they are known in foreign countries, are numerically the strongest disciplined force available for any national activity. There are even cases where they retire at the age of 32-20+12. I am sure Babuji will understand me. When we declare them too old to work and ask them to retire, they are actually too young to retire. So, apart from pension, it is high time that we took a comprehensive look at what is to be done about this numerically strongest force in this country.

There are nearly 20 million ex-servicemen in this country and *pro rata*, Punjab, Haryana, U.P. and Kerala have got the highest number of ex-servicemen. In Kerala there are more than 2.5 lakhs. So, instead of thinking too much about pension, which is of course important, their discipline, their training and help must be properly utilised. So, may I know from the hon. Minister whether the Government thinks in terms of a comprehensive plan for the gainful employment of these ex-servicemen. and whether they will publish a white Paper as to how best these ex-servicemen can be utilised in the matter of land allotment, gainful employment and various activities where their skill and discipline can be made best use of by the country?

SHRI JAGJIVAN RAM: The hon. Member has put a very eloquent question, but I have admitted that it is a very difficult and complicated problem. Nearly 50,000 soldiers are demobilised every year and looking at the employment situation in the country as a whole, the problem of unemployment that the country is facing, it is not a very easy task to absorb all of them in gainful employment. Though we have made certain reservations in Government service, especially in Class III and Class IV, and also in the public and private sectors, it has not been possible to absorb all of them, because if you do it here, you will be accentuating unemployment, educated and uneducated both, in the non-army sector.

Perhaps the hon. Member could not follow what I said earlier as I was answering in Hindi. I think his anxiety would have been met to some extent if he had followed it. As I have explained, the qualification required for posts of officers in many cases in both the Government and the private sector is graduation, and most of our officers are not graduates. So, we have a scheme of giving them specialised training in management and other things, so that they can become more employable in the private or public sector.

So far as jawans are concerned, we have reached the stage where, except in one or two States, we cannot think of allotting land to them. Therefore, we have to find avenues for more and more self-employment. Therefore, we have introduced a scheme that six months before they are to be demobilised we give them training in some art or creft so that after demobilisation, if it is not possible to find employment, they can start some industry, or some enter-prise for self employment.

I may assure the hon. Member that nobody retires at the age of 32 since the period of colour service has now been raised to 15 years.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि भूतपूर्व सैनिकों को सरकार प्रशिक्षण देना चाहती है जिससे वे अपने उद्योग चला सकें। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें उन उद्योगों को चलाने के लिए समुचित धन-राशि कम ब्याज पर सरकार उपलब्ध करेगी और एक ही प्रार्थना-पत्र देने पर उन्हें बैंक से लोन मिल जाए क्या इसकी भी व्यवस्था की जाएगी? क्या सरकार बैंकों के द्वारा ही या अलग से भी लोन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगजीवन राम : बैंकों से लोन दिलाने की व्यवस्था की गई है लेकिन एक ही दरख्वास्त देने पर लोन मिल जायगा यह नहीं कहा जा सकता है। बैंकों की दक्षता जैसे-जैसे बढ़ेगी वैसे-वैसे यह होता जाएगा। लेकिन लोन दिलाने का प्रबंध है।

श्री शिव नारायण : देश में बहुत से नौजवान बेकार घूमते है। आवश्यकता पड़ने पर ये जो रिटायर्ड ट्रैंड आदमी मिलिटरी वाले है इसको हर कालेज स्कूल आदि में, प्राइवेट और सरकारी में ड्रिल मास्टर एप्वाइंट कराने में सरकार मदद करेगी ?

श्री जगजीवन राम : इसका मतलब यह होगा कि जो स्कूलों के ड्रिल मास्टर अभी है, उनको हटाना पड़ेगा।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: In view of the fact that the period of service of the Army personnel bright from a Jawan to a colonel is much less than the period of service in the civil side and in view of the fact that it is necessary to preserve the ability of the forces to defend our country, will the Defence Minister consider some scheme of extending the period of retaining them as reserves and include that period also into their service so that they can get normal pension which a civil servants gets?

SHRI JAGJIVAN RAM: In view of the fact that the soldier or officers retire earlier than what they do in the civil side, weightage is given in calculating their pension as compared to civil side. The amount of pension that is given in defence forces is comparable to the civil side. It is not less.

We had a scheme of Reservists but that has not been found popular. Therefore, we have done away with it.

SHRI GANGA SINGH: Sometimes it happens that the military personnel retire at an early age. I cite my own example. I retired before the age of 21. Whether the Government will think of relaxing the age limit in All India Services like IAS, IPS for such persons?

SHRI JAGJIVAN RAM: That has already been done.

SHRI G. S. REDDI: At some places the soldires were allotted lands but at lower levels they are finding it difficult to take occupation of those lands. Will the Government help them in this regard?

SHRI JAGJIVAN RAM: I shall bring it to the notice of the State Government.

Demand of Bonus by Employees of H.M.T. Watch Factory Bangalore

*554. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Employees of the HMT Watch Factory, Bangalore have appealed to the Central Government to meet the workers demand for more than 20 per cent bonus and pay the arrears of the bonus for the year 1975-76;

(b) whether the Union of the workers have also urged the Centre to direct the factory management to start negotiations with workers on the annual bonus based on productivity; and

(c) if so, the reaction of Central Government thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) As a result of the operation of the Payment of Bonus Act as amended in 1976, the payment of annual bonus linked with productivity is subject to a ceiling of 20 per cent of the wages of the employees. Accordingly the